>

Title: Regarding non-implementation of decision taken by the Government to export sugar from the country.

श्री हरिभाऊ जावले (रावेर): सभापति महोदया, चीनी निर्यात रोकने से चीनी उत्पादन मिल और गन्ना उत्पादक किसानों की जो क्षति हो रही है, उससे गंभीर चिंता हो रही है। इस मामले को उठाने की आपने अनुमति दी, मैं आपका आभारी हूं। केन्द्र सरकार ने 5 लाख टन चीनी का निर्यात करने हेतु अनुमति प्रदान की थी। लेकिन उसके बाद भी इस निर्णय का कार्यान्वयन स्थगित रखा गया है। इस निर्णय के परिणामस्वरूप सहकारिता क्षेत्र में चीनी उत्पादक मिलों को प्रतिमाह 200 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है, उससे गन्ना उत्पादक किसानों के प्रति गहरी चिंता व्यक्त की जा रही है। मेरा मानना है केन्द्र सरकार ने जो यह चीनी का निर्यात रोक दिया है, इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। खासकर जो प्राइवेट फैक्टरीज हैं, कुछ 8-10 फैक्टरीज देश में हैं, वे अंडर लाइसेंस निर्यात कर रही हैं और जो सरकारी चीनी मिलें हैं, उनका निर्यात बंद कर दिया है। इस साल इस मौसम में चीनी का उत्पादन कम से कम 260 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है। उसमें 50 लाख मीट्रिक टन पहला स्टॉक अपने पास है। देश की पूरी मांग 225 लाख मीट्रिक टन हो सकती है और जो बाकी 60-70 लाख मीट्रिक टन बची है, उसे निर्यात करना ही चाहिए। अगर यह निर्यात नहीं किया तो उससे चीनी मिलों का भी नुकसान हो रहा है और जो गन्ना उत्पादक किसान हैं, उनको भी उचित दाम नहीं दे सकते।

19.00 hrs.

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि निर्यात तुंत शुरू कर दिया जाए। इसे शुरू करने के बाद ही हम गन्ना किसानों को अच्छा दाम दे सकते हैं।